पर्यटन विभाग के बजट अनुमानों में 3.70 करोड़ रुपये का एक प्रावधान किया गया है । इसमें पूंजीगत खर्च की राशि 168.50 लाख रुपये है, जिसे स्पिल ओवर स्कीमों और जारी स्कीमों (50.00 लाख रुपये) तथा नई स्कीमें (118.50 लाख रु०) पर खर्च किया जाना है ।

(ग) पर्यटन आधारिक संरचना का विकास यात्रा परिपथ संकल्पना के आधार पर एकीकृत ढंग से प्लान किया गया है । राज्य सरकारों / संघ शासित क्षेत्रों से परामर्श करके 61 यात्रा परिपथ अभिनिर्धारित किए गए हैं जिनमें 441 केन्द्र शामिल हैं । केन्द्रीय, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों में उपलब्ध संसाधनों का एकत्र करते हुए एकीकृत और अवस्थानुसार ढंग से इन केन्द्रों के विकास का कार्य प्रारम्भ किया जाएगा ।

Import of Indian Tea stopped by foreign countries

3206. SHRI ANANTHA RAMULU MALLU: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether some foreign countries have stopped the import of Indian tea recently;

(b) if so, the names of such countries; and

(c) the reasons thereof as well as the reaction of Indian Government thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. A. SANGMA): (a) to (c). Among the major tea import markets Libya is the only market which has not purchased any teas from India so far during the current financial year. This is only a temporary phase reportedly due to their over stocking of tea in the previous year and they are likely to resume their purchases during the ensuing financial year.

Boosting of Engineering Exports

3207. SHRI BHIKU RAM JAIN: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a slow-down in engineering exports in the absence of the cash compensatory support scheme; and

(b) the steps proposed to be taken by Government in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. A. SANGMA): (a) and (b). The present regime of cash compensatory support was introduced for a period of three years from 1-4-1979 and is valid upto 31-3-1982. Therefore, there is no question of export of engineering goods slowing down in the absence of CCS scheme. Continuation of CCS scheme beyond 31-3-1982 is under the active consideration of the Government.

केनरा बैंक के अनुसुचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों द्वारा दिया गया ज्ञापन

3208. **श्री राम विलास पासवान :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केनरा बैंक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं के बारे में अपने संघ के माध्यम से उन्हें और अन्य उच्च अधिकारियों को 15 फरवरी, 1982 को एक ज्ञापन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।